

छह घंटे पूछताछ के बाद उर्मिला ने सौंपी रिकार्डिंग, एक और ऑडियो वायरल अंकिता भंडारी के माता पिता ने सीएम धामी से की मुलाकात

देहरादून। उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी नेताओं के खुलासे को लेकर राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा हुआ है। वहीं अब इस मामले को लेकर धामी सरकार ने भी अंकिता के मातापिता को जनभानाओं के अनुरूप संजीदगी से जांच कराने का आश्रय दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में स्वर्गीय अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह

सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अभिनेत्री उर्मिला सनावर का सोशल मीडिया पर बुधवार को एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में उर्मिला ने कहा कि दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूछताछ की। जिसमें मैंने पूरा सहयोग किया और सभी सवालों के जवाब दिए। इसके साथ ही जो भी साक्ष्य थे वो भी उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि अंकिता के साथ न्याय होना



मिले। उर्मिला सनावर आज हरिद्वार में एसआईटी प्रभारी के सामने पेश हो सकती हैं। इस पूछताछ में दोनों प्राथमिकी (नेहरू कॉलोनी और डालनवाला में दर्ज) के विवेचना अधिकारी शामिल रहे। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि उर्मिला को बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उर्मिला ने दोनों जांच अधिकारियों को सुरेश राठौर और उनके बीच हुई बातचीत की ऑडियो क्लिप दी हैं। इसे वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। एसएसपी ने बताया कि उर्मिला ने अपनी सुरक्षा के संबंध में जो प्रार्थनापत्र दिया था उस पर एलआईयू से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि एक के बाद एक चार प्राथमिकी दर्ज होने पर उर्मिला एकाएक शांत हो गई थीं। उन्होंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था। मंगलवार को उनकी सोशल मीडिया पर

एक पोस्ट अचानक वायरल होने लगी। उर्मिला ने लिखा था कि वह उत्तराखंड आ रही हैं और अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित साक्ष्य एसआईटी को उपलब्ध कराएंगी। उर्मिला स्वामी दर्शन भारती के साथ मंगलवार रात करीब नौ बजे देहरादून पहुंची थीं। सूत्रों के अनुसार सुबह होते ही उर्मिला को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उर्मिला से इस मामले के संबंध में कई सवाल किए गए। उनके पास जो ऑडियो-वीडियो हैं उनकी कॉपी भी पुलिस ने अपने कब्जे में ली है। पुलिस के अनुसार ऑडियो में बातचीत किस आधर पर हो रही है क्या ऐसे कोई साक्ष्य हैं जिससे यह बात सिद्ध हो सके इस बारे में उर्मिला के पास कोई जवाब नहीं था। उर्मिला के पास केवल एक ऑडियो रिकार्डिंग और कुछ वीडियो मिले हैं।

दुष्प्रचार के लिए प्रदेश की जनता से मांगे माफी : धामी

देहरादून। अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर जारी रहेगी। पूरे मामले की एसआईटी लगातार जांच कर रही है। सीएम ने कहा कि कानून द्वारा की गई हर जांच पर सरकार भी विचार विमर्श कर रही है, जिसके बाद सरकार भी इस पर निर्णय लेगी। लेकिन इस पूरे मामले में पिछले 15 दिनों से जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा था उससे राज्य में चल रही विकास योजनाएं चल रही थी, उस प्रकरण के कारण लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया। सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह से कथित ऑडियो एक फिर बाहर निकला है उससे साफ होता है कि इस प्रकरण में पिछले दिनों से षड्यंत्र हो रहा है और उन्हें प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सीएम ने ऑडियो वायरल करने वाली उर्मिला और सुरेश की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनके कारण प्रदेश का माहौल खराब हुआ है, इसलिए उनको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

वीडियो भी उन्होंने खुद रिकॉर्ड किए हैं। अब इन्हीं वीडियो और ऑडियो को दिखाने के लिए उर्मिला बृहस्पतिवार को एसआईटी प्रभारी के सामने पेश होंगी। बहलहाल अब पुलिस के समक्ष कथित वीआईपी के नाम लेने वाले सुरेश राठौर से पूछताछ का दबाव बढ़ गया है। उर्मिला और सुरेश की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। हालांकि इस ऑडियो में हो रही बातचीत को अंकिता हत्याकांड के मामले से अलग बताया जा रहा है। जिसमें किसी डकैती को लेकर आते हो रही हैं। इस ऑडियो में एक व्यक्ति एक महिला पर चर्चित मामले में

एक बड़े नेता का नाम न लेने पर धोखेबाजी की बात कह रहा है। व्यक्ति कहते हुए सुना जा रहा है कि तुमने तीन लोगों में किसी एक के कहने पर पर नेता का नाम नहीं लिया। महिला एक बड़े का नाम लेते हुए कहती है कि तुम उसको बर्बाद करना चाहते थे। वह कहती है तुम दबाव बनाकर मुझे आरोपी बनाकर हमारे ऊपर ब्लैकमेलिंग और मानहानि लिखवाकर जेल भेज देते। व्यक्ति आगे बातचीत में धोखेबाजी की बात करते हुए कहता है कि... वायदा हुआ था कि नाम लिया जाएगा। महिला कहती है मीडिया ने जो पूछा उसका जवाब दिया। इस पर वह व्यक्ति मीडिया को लेकर भी अमर्यादित शब्द कहता हुआ सुनाई देता है।



भंडारी व माता श्रीमती सोनी देवी ने भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने प्रकरण से संबंधित अपने मतव्य एवं भावनाएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना और आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पीडित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पीडित परिवार को हर संभव सहयोग एवं उनकी मांगों पर

चाहिए क्योंकि वो पूरे देश की बेटी थी। उसके लिए भले ही सीबीआई या कोई अन्य उच्च स्तरीय जांच क्यों न करनी पड़े। अगर मेरा नार्को टेस्ट कराने की जरूरत हो तो उसके लिए तैयार हूँ। सनावर ने कहा कि हमारा नाम राजनीति से जोड़ जा रहा है। कोई कह रहा है कि मैं कांग्रेसी हूँ तो कोई कह रहा है कि भाजपा के गुटों में बंटी हुई हैं। उन्होंने अंकिता मामले को लेकर राजनीति न करने की लोगों से गुहार लगाई। साथ ही कहा कि मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि अंकिता को न्याय

विकास योजनाओं के लिए 227.73 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन

देहरादून (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत रोडी बेलवाला क्षेत्र पुनरुद्धार विकास कार्य हेतु 59.11 करोड़ की योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा गैरसैण (चमोली) विधानसभा परिसर, भराडीसैण में सम्पूर्ण चाहरदीवारी एवं मुख्य गेट के निर्माण कार्य हेतु वास्तविक लागत 9.87 करोड़ के सापेक्ष द्वितीय किशत के रूप में 40 प्रतिशत अर्थात् 3.95 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत राज्य को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल को 09 योजनाओं हेतु आवास विभाग, उत्तराखण्ड को आर्बिट्रट धनराशि 164.67 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस धनराशि का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने दी सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे स्वायत्तशासी संस्थाओं यू-कॉस्ट एवं यू-सैक के नियमित कार्मिकों के लिए महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर दिनांक 01 जनवरी, 2025 से 55 प्रतिशत तथा 01 जुलाई, 2025 से 58 प्रतिशत किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

आंदोलन राजनीति से प्रेरित, दोनों का करारें नार्को टेस्ट : दर्शन भारती

देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर ऑडियो वायरल करने के बाद देहरादून पहुंची अभिनेत्री उर्मिला सनावर से जुड़े मामले में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। नौ दिन बाद उर्मिला को देहरादून लाने वाले स्वामी दर्शन भारती ने इस पूरे विवाद के लिए पूर्व विधायक सुरेश राठौर को जिम्मेदार ठहराया है। स्वामी दर्शन भारती का दावा है कि राठौर के दबाव में ही उर्मिला ने अस्थायी तौर पर दुष्यंत का नाम लिया, जबकि असली दोषी कोई और है। स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि यदि सुरेश राठौर की ओर से इस तरह के बयान नहीं दिए जाते, तो न तो यह मामला तूल पकड़ता और न ही इतना बड़ा हंगामा होता। उन्होंने मांग की है कि सच्चाई सामने लाने के लिए सुरेश राठौर और संबंधित व्यक्ति दोनों का



नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए, जिससे पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ सके। भारती ने कहा कि दुष्यंत गौतम और सुरेश राठौर के बीच पुरानी राजनीतिक दुश्मनी रही है। दोनों एक ही वर्ग से आते हैं जो अलग अलग पीठों के मठाधीश भी बने हुए हैं। हालांकि, जांच एजेंसियों को लेकर स्वामी दर्शन भारती का रुख सवालों के

घेरे में है। उन्होंने एसआईटी जांच से दूरी बनाते हुए इसे राजनीतिक करार दिया है। इतना ही नहीं, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए चल रहे आंदोलन को भी उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया, जिस पर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पूरे मामले में बार-बार बदलते

बयान, लंबी चुप्पी और कथित 'स्क्रिप्टेड रोल' जैसे आरोपों ने केस को और उलझा दिया है। वहीं, स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि सभी जांचों में पुलिस को सहयोग किया जाएगा और उर्मिला सनावर देहरादून में सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उर्मिला पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगी। सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई यूजर्स का कहना है कि स्वामी दर्शन भारती के बयान स्थिर न होकर भ्रमित करने वाले हैं और वह जांच से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं, कुछ लोग मामले की निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियों की नजर पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है।

माल्टा मिशन से मिलेगी पहाड़ी किसानों को नई पहचान

माल्टा महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री ने किया विभिन्न उत्पादों का अवलोकन



देहरादून (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सीमा द्वार स्थित आईटीबीपी स्टेडियम में आयोजित दो दिवसीय माल्टा महोत्सव में शिरकत की। सेवा संकल्प (धारिणी) फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों से मुलाकात की और माल्टा व नींबू की खटाई का स्वाद लिया। इस

दौरान उन्होंने राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में माल्टा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाते हुए 'माल्टा मिशन' शुरू करने की घोषणा की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य माल्टा के उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ

उसके विपणन और मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडिशन) को मजबूती प्रदान करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल से पर्वतीय क्षेत्रों के काश्तकारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और स्थानीय फलों को राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार केवल माल्टा ही नहीं, बल्कि कीवी, सेब, आड़ू, पुलम और

नींबू प्रजाति के अन्य स्थानीय फलों के उत्पादन को भी प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने माल्टा महोत्सव जैसे आयोजनों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मंच किसानों को सीधे उपभोक्ताओं और बाजार से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस अवसर पर आईजी आईटीबीपी संजय गुज्याल सहित कई अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की 80वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि

देहरादून (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गढ़ीकैंट स्थित हरबंस कपूर मेमोरियल सामुदायिक भवन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर की 80वीं जयंती के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरबंस कपूर का व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव मार्गदर्शक और प्रेरणादायक बनी रहेगी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरबंस कपूर ने अपने पूरे जीवन में जनता के हितों को सर्वोपरि रखा। उनका समर्पण और



सादगी उन्हें एक विशिष्ट जननेता बनाती थी। मुख्यमंत्री ने उनके साथ बिताए समय को याद करते हुए कहा कि वे संवेदनशीलता के प्रतीक थे और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते थे। राज्य के विकास से जुड़े हर मुद्दे पर उनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रहा, जिसे उत्तराखंड कभी नहीं भूलेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हरबंस कपूर को अपना राजनीतिक गुरु बताया। उन्होंने कहा कि आज वे राजनीति में जिस मुकाम पर हैं, उसमें कपूर का बड़ा योगदान है। उन्होंने कपूर को एक आदर्श जननेता बताते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए जनसेवा के कार्य अनुकरणीय हैं। इस अवसर पर विधायक सविता कपूर और दायित्वधारी श्याम अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

श्रद्धा हमारे अहंकार को दूर करती है: हरि चैतन्यपुरी

गढ़ीनेगी (उद संवाददाता)। श्री हरि कृपा पीठाधीश्वर व संत स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज ने यहाँ श्री हरि कृपा धाम आश्रम में उपस्थित विशाल भक्त समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि श्रद्धा, विश्वास और प्रेम तीनों ही यदि जीवन में उतर जाए तो संतोष और सच्चे आनंद की अनुभूति होने लगती है। यह तीनों कि वह त्रिवेणी है जो जीवन यात्रा में निरसता हटाकर जीवन में सरसता भरती है तथा हमारे अंतःकरण की मलीनता को दूर करती है। हमें अश्रद्धा, अविश्वास और वैर से सदैव दूर रहना चाहिए, तभी जीवन में सच्ची सुख शांति मिल सकती है। उन्होंने कहा यदि इंसान शांतिपूर्वक जीना चाहता है तो उसे श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। आधुनिक जीवन शैली में रची बसी जटिलताएँ और तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए

यदि हम इन तीन शब्दों के महत्व को जान लें तो कलह-क्लेश, दुख-शोक और कष्ट आदि सब मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आध्यात्मिक शक्ति

करती है। श्रद्धावश ही हम दूसरों का हृदय से सम्मान करते हैं। श्रद्धा का प्रतिफल हमें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। श्रद्धा का परिणाम सदैव शुभदायक और

श्रद्धालुओं के सभी संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। यदि हमारा मन निर्मल है हमारी मनोभूमि में अवगुणों का प्रदूषण नहीं है। और हम दुर्व्यसनों के शिकार नहीं हैं तो

पत्र बन जाते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका स्वरूप हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा सदैव अंतःकरण के अनुरूप होती है, इसलिए मनुष्य को सदैव सात्त्विक श्रद्धा से युक्त रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि परमात्मा का स्मरण हृदय से करते हुए कर्म करें। जगत की यथासामर्थ्य सेवा तथा परमात्मा व संतों से प्रेम करें। उन्होंने कहा कि सद्भाव मुक्ति व असद्भाव पतन का मार्ग है। यथासंभव व्यर्थ के उलझाव व टकराव से बचने का प्रयास करें। जहाँ मान व कपट को आश्रय मिल जाता है। आज समाज सुधारकों की नहीं, समाज सेवकों की आवश्यकता है। हमारे आंतरिक भाव जिस प्रकार से होंगे धीरे-धीरे बाहरी चेष्टाएँ भी वैसी होने लगेंगी। जब कोई व्यक्ति निष्पक्ष व शांत होकर अपनी

अंतरात्मा से परामर्श लेता है तो उसे सदैव सत्य परामर्श ही प्राप्त होता है। संसार में किसी को भी, कभी भी, किसी प्रकार से भी दुख, भय या क्लेश नहीं पहुंचाना चाहिए। तथा ना ही पहुंचाने की प्रेरणा या इच्छा करनी चाहिए। सदैव सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। जिस सत्य में कपट होता है वह सत्य, सत्य नहीं समझा जाता। अपने धारा प्रवाह प्रवचनों से उन्होंने सभी को मंत्रमुग्ध व भाव विभोर कर दिया। सारा वातावरण "श्री गुरु महाराज," कामां के कन्हैया व लाठी वाले भैया की जय जयकार से गूँज उठा। इससे पूर्व श्री महाराज जी के श्री हरि कृपा धाम आश्रम गढ़ीनेगी काशीपुर पधारने पर बड़ी संख्या में भक्तों ने भव्य हार्दिक स्वागत किया। श्री महाराज जी ने श्री हरेश्वर महादेव का महा अभिषेक किया व अपने दर्शनों व दिव्य अमृत वचनों से श्रद्धालुओं को कृतार्थ किया।



के संरक्षण और संवर्धन के लिए मन में श्रद्धा होनी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा हमारे अहंकार को दूर

मंगलकारी होता है। इसलिए श्रद्धावान व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी अपने आत्मबल के सहारे टिका रहता है। सच्चे

श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के अंकुर पल्लवित होने में देर नहीं लगती। हम शीघ्र ही श्रद्धान्त हो जाते हैं। भगवान के कृपा

बहुदेशीय शिविर में ग्रामीणों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ

नैनीताल (उद संवाददाता)। धामी सरकार की जनसेवा पहल के अंतर्गत जनपद के विकासखंड ओखलकांडा की न्याय पंचायत सुनकोट के ढोलीगांव में 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' बहुदेशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर स्थानीय जनता को केंद्र और राज्य सरकार की जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी दी और मौके पर ही विभागीय सेवाएँ प्रदान कीं। इस दौरान लगभग

वितरित कीं। इसी प्रकार होम्योपैथी विभाग द्वारा 49 और आयुर्वेदिक विभाग द्वारा 66 लोगों की जांच कर उपचार दिया गया। राजस्व विभाग ने तत्परता दिखाते हुए विभिन्न प्रकार के 33 प्रमाण

18 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया। विद्युत विभाग ने 6 नए संयोजन और बिल संशोधन संबंधी कार्यों का निस्तारण किया। शिविर में दर्जा राज्यमंत्री शांति महारा और भीमताल



212 लोगों ने शिविर का सीधा लाभ उठाया। शिविर में क्षेत्रीय जनता ने व्यक्तिगत और क्षेत्र के विकास से संबंधित समस्याएँ अधिकारियों के सम्मुख रखीं। कुल प्राप्त शिकायतों में से 43 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। स्वास्थ्य सुविधाओं के मोर्चे पर चिकित्सा विभाग ने 104 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाएँ

पत्र जारी किए, जबकि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 51 प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। कृषि और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यान विभाग ने 19 काश्तकारों को लाभान्वित किया, जबकि कृषि विभाग ने 16 कृषकों को कृषि यंत्र वितरित किए। पशुपालन विभाग ने 15 पशुपालकों को योजनाओं से जोड़ा और बाल विकास विभाग द्वारा

विधायक राम सिंह कैड़ा ने शिरकत कर ग्रामीणों की समस्याएँ सुनीं। इस अवसर पर क्षेत्र प्रमुख केडी रूवाली, जिला पंचायत सदस्य बहादुर सिंह नगदली, भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेश नयाल, मनोज सुयाल, जिला सहायक निबंधक डीएस नपलच्यल और खंड विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

राजनगर में मिल्क प्लांट के खिलाफ धरने पर बैठे किसान

शक्तिफार्म/शक्तिफार्म क्षेत्र के ग्राम राजनगर में प्रस्तावित मिल्क पाउडर व आइसक्रीम प्लांट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को ग्रामीणों ने प्लांट निर्माण के विरोध में धरना शुरू कर दिया और सरकार से इसे किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने की मांग की। धरना दे रहे ग्रामीणों का कहना है कि जिस भूमि पर

पालिकाध्यक्ष हरीश दुबे धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन दिया। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते

अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि गांव राजनगर की पांच एकड़ भूमि को जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2023 में दुग्ध विभाग को हस्तांतरित किया गया था। इसी भूमि



स्थापित किया जा रहा है, उस पर वे पिछले कई दशकों से खेती करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने दावा किया कि उक्त भूमि निरोध चंद्र व्यापारी, रतन मंडल, उषेन्द्र नाथ मंडल एवं नित्यानंद मंडल के नाम पर वर्ग-20 में दर्ज है। ऐसे में बिना किसानों की सहमति भूमि पर प्लांट लगाया जाना अन्यायपूर्ण है। धरने को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नवतेज पाल सिंह, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष उत्तम आचार्य तथा पूर्व

हुए कहा कि सरकार विकास के नाम पर किसानों की जमीन छीनने का प्रयास कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं, दुग्ध विभाग के

पर नाबार्ड की सहायता से मिल्क पाउडर एवं आइसक्रीम प्लांट की स्थापना की जा रही है। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि यह मामला किसानों और सरकार के बीच किस दिशा में जाता है।

शादी का झांसा देकर चार साल तक दुष्कर्म का आरोप

शक्तिफार्म। शक्तिफार्म क्षेत्र के एक गांव से शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक ने चार साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इस दौरान तीन बार उसका गर्भपात भी कराया। चौथी बार गर्भवती होने पर आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता के अनुसार, उसका तिलियापुर निवासी कुलदीप के साथ पिछले चार वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस रिश्ते की जानकारी दोनों परिवारों को थी और दोनों का विवाह तय होने की बात भी कही जा रही थी। युवती का आरोप है कि इसी भरोसे पर कुलदीप ने उससे लगातार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि इस दौरान वह तीन बार गर्भवती हुई और हर बार आरोपी ने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। जब वह चौथी बार गर्भवती हुई और उसने कुलदीप से विवाह करने की बात कही, तो आरोपी ने यह कहकर इंकार कर दिया कि उसके परिजन शादी के लिए तैयार नहीं हैं। युवती का कहना है कि जब वह इस संबंध में कुलदीप के घर पहुंची, तो उसके पिता प्रेम सागर ने उसे घर से भगा दिया और विवाह कराने से साफ मना कर दिया। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पीड़िता ने न्याय की मांग करते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। पुलिस द्वारा चार नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर मामले की जांच कि जा रही है।

डीएम ने की जेंडर सेंसिटाइजेशन अभियान की समीक्षा

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में जेंडर सेंसिटाइजेशन (लैंगिक संवेदीकरण) को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की प्रगति जांची गई। जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि अभियान से जुड़ी समस्त सूचनाएं एक सप्ताह के भीतर पोर्टल पर अपलोड की जाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि जनपद में बीते 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक कुल 114 गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा 31, महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा 27 तथा अन्य माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए, जिससे कुल 15979 लाभार्थी लाभान्वित हुए। वर्तमान में विभिन्न विद्यालयों और उद्योगों में पॉक्सो अधिनियम, बाल सुरक्षा तथा महिला सुरक्षा के संबंध में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा महिला समूहों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जा रहा है, जिसके तहत 191 जेंडर प्लेज और लैंगिक हिंसा पर आधारित 507 सत्र आयोजित किए गए हैं।

गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर निकला भव्य नगर कीर्तन



रामनगर (उद संवाददाता)। गुरु गोविंद सिंह की 359वीं जयंती के अवसर पर गुरु मत प्रचार कमेटी के तत्वाधान में नगर में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरा क्षेत्र गुरुवाणी के स्वर्ण से गुंजायमान रहा और संगत ने भारी उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। पांच प्यारों की अगुवाई में निकली

इस शोभायात्रा का जगह-जगह पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया गया। गुरु मत प्रचार कमेटी के उपाध्यक्ष हरमिंदर सिंह आनंद संदी ने बताया कि इस वर्ष महानगर संकीर्तन की शुरुआत पीरुमदारा गुरुद्वारे से हुई। यह कीर्तन मुख्य मार्ग से होते हुए नगर के मुख्य बाजार में पहुंचा और वहां भ्रमण के उपरांत रामनगर गुरुद्वारे

पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में गुरुद्वारे में विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। नगर कीर्तन में आसपास के सभी गुरुद्वारों की संगत ने हिस्सा लिया। विशेष आकर्षण के रूप में बाहर से आए कलाकारों ने गतका (सिख मार्शल आर्ट) का

हैरतअंगेज प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभिन्न समुदायों के लोग भी शामिल हुए।

डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

काशीपुर। अनियंत्रित डंपर की चपेट में आकर अस्पताल कर्मी की हुई मृत्यु के मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के बारे में पुलिस को तहरीर देकर ग्राम चांदपुर, गिरजा विहार कॉलोनी, इंदुमती फॉर्म के पास, प्रतापपुर निवासी राहुल सिंह पुत्र प्रभु चरण ने बताया कि उसका 26 वर्षीय

भाई रोहित केवीआर अस्पताल में कार्यरत था। बीते एक जनवरी को रात्रि लगभग 9:30 बजे वह अपने दोस्त की मोटरसाइकिल संख्या यूके18के/8645 से कुंडेश्वरी से ड्यूटी पर अस्पताल की ओर जा रहा था इसी दौरान रास्ते में मालवा फॉर्म के पास सामने से चौती की ओर से तेज गति चले आ रहे डंपर संख्या यूपी 22एटी/3789 के चालक नाम पता अज्ञात ने तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर

मारकर उसके भाई को गंभीर रूप से लहुलुहान कर दिया। एक्सीडेंट की इस घटना में बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के तत्काल बाद आरोपी डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटना के इस मामले में मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर आरोपी डंपर चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए।

जगदीश कलर लैब

टंडन फोटो स्टूडियो

पासपोर्ट फोटो तुरन्त प्राप्त करें

जन्मरेकर्ड सुविधा भी उपलब्ध है।

मोबाइल, डिप, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, सीडी आदि डिजिटल कार्य तुरन्त बनवायें।

काशीपुर बाईपास रोड,

गुरुजानक कल्याण इण्टर कालेज के सामने गली में, रूद्रपुर
E-mail: jagdishcalourlab@gmail.com
Web: jagdishcalourlab.com

05944-246817

शिविर में प्रशासन और जनता के बीच हुआ सीधा संवाद

शिविर में 82 समस्याएं पंजीकृत हुई जिसमें से 14 का मौके पर ही समाधान किया गया

खटीमा (उद संवाददाता)। जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत बुधवार को विकास खण्ड खटीमा के न्यायपंचायत खेतलसंडा खाम के अशोक फार्म बागोलिया में सीडीओ दिवेश शासनी की अध्यक्षता में भव्य बहुदेशीय शिविर आयोजित हुआ। जन जन शिविर में मुख्य अतिथि दर्जा मंत्री उत्तम दत्ता व नगर पालिका अध्यक्ष रामेश चंद्र जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का जनता के द्वार जाकर समाधान करना है, ताकि जनता को अनाआवश्यक विभागों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा जनसमस्याओं का निराकरण सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए शिविर में प्राप्त शिकायतों व समस्याओं

का तत्काल निस्तारण किया जाये। उन्होंने अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को शत-प्रतिशत लाभ देने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने कहा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की श्रेष्ठ पहल है, इसके लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जनता से इन जन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील भी की। शिविर में 25 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जाँच कर मरीजों को द्वारा भी वितरित की गई, एक्सरे भी किए गए। शिविर में 1538 लोगों को विभिन्न विभागों की योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में

स्वास्थ्य विभाग द्वारा 655 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण जांच, होम्योपैथिक द्वारा 52 राशन कार्ड ई केवाईसी, 05 नए नाम जोड़े गए, 42 आधार कार्ड अपग्रेड



एवं दवा वितरण, 52 एक्सरे, 21 आयुष्मान कार्ड बनाए, श्रम विभाग द्वारा 16 श्रम कार्ड बनाए, 45 लाभार्थियों को टूल किट, कंबल, छाता, 01 मृत श्रमिक का 02 लाख का चेक वितरण, 03 बच्चों को

शिक्षा सहायता चौक वितरण, पूर्ति विभाग द्वारा 52 राशन कार्ड ई केवाईसी, 05 नए नाम जोड़े गए, 42 आधार कार्ड अपग्रेड



व नए बनाए गए जबकि समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन के 22 फार्म भरवाए गए एवं एक दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया, 08 कन्या विवाह अनुदान, 10 जन्ममृत्यु प्रमाणपत्र, 08 आयु

जाति स्थाई प्रमाणपत्र जारी किए गए। शिविर में 05 गर्भवती महिलाओं की गोदभराई व 02 बच्चों की अन्नप्राशन किया गया, सेवायोजन विभाग द्वारा 07 युवाओं को जानकारी दी गई। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 45 बीपीएल व 20 जाब कार्ड बनाए गए, शिक्षा विभाग द्वारा 05 छात्राओं को साइकिल चेक, 02 को ड्रेस वितरण, कृषि विभाग द्वारा 01 लाभार्थी को 04 लाख का ट्रैक्टर खरीद अनुदान चेक, 03 मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए, पशुपालन विभाग द्वारा 173 को जानकारी दी व दवा वितरण, उद्यान विभाग द्वारा 14 लाभार्थियों को बीज व उपकरण वितरण, डेरी विभाग द्वारा 23, मत्स्य विभाग द्वारा 24 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। जबकि विधि क सेवा प्राधिकरण द्वारा 75 लोगों को

जानकारियां दी, विधुत विभाग द्वारा 11 शिकायतों का निस्तारण किया गया। शिविर में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी, अध्यक्ष नगर पालिका खटीमा रामेश चंद्र जोशी, सांसद प्रतिनिधि रविन्द्र राणा, पूर्व मंत्री अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत, पूर्व सहकारी बैंक अध्यक्ष दान सिंह रावत, सतीश भट्ट, उपजिलाधिकारी तुषार सैनी, तहसीलदार वीरेंद्र सजवान, नोडल अधिकारी/मुख्य शिक्षाधिकारी के एस रावत, ई ई एम आई सुशील कुमार, समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध, खंड विकास अधिकारी संजय कुमार गांधी, सेवायोजन अधिकारी राजेश दुर्गापाल, प्रोवेशन अधिकारी व्योमा जैन, जी एम दुग्ध राजेश मेहता, परियोजना अधिकारी उडेदा संदीप सैनी तथा अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

सरकारी संपत्तियों से तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने जिला सभागार में विभिन्न विभागों की भूमि और परिसम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाने के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि जिन विभागों ने अभी तक अपनी विभागीय परिसम्पत्तियों की संपत्ति पंजीकृत तैयार नहीं की है, वे 15 दिन के भीतर इसे पूर्ण कर लें। साथ ही, सभी संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग और निर्धारित एप पर पोलिगन तैयार करना सुनिश्चित करें। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों ने पोलिगन तैयार

विभागों को 15 दिन के भीतर संपत्ति पंजीकृत और जीआईएस मैपिंग पूर्ण करने की चेतावनी

कर लिया है, वे उसे समय-समय पर अपडेट करते रहें ताकि शासन स्तर पर संपत्तियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट रहे। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जिन विभागों की परिसम्पत्तियों पर अतिक्रमण है, उसे तत्काल हटाया जाए। सभी विभाग अपनी संपत्ति अतिक्रमण मुक्त होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करें। उन्होंने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एक माह के भीतर परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें

कि किस विभाग के नाम कितनी भूमि दर्ज है। बैठक में परिसम्पत्तियों के कुशल प्रबंधन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि विभागीय संपत्तियों का रखरखाव और सदुपयोग इस तरह किया जाए कि वहां अतिक्रमण को कोई गुंजाइश न रहे। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए जिससे यह पता चल सके कि किस परिसम्पत्ति को किस सार्वजनिक कार्य में उपयोग में लाया जा सकता है। नगर निकायों को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्रों में नालियों,



नालों और सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए निरंतर अभियान चलाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र, उत्तराखंड कृषि उत्पादन

विपणन बोर्ड की महाप्रबंधक निर्मला बिष्ट, ओसी गौरव पाण्डेय, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता पीके दीक्षित, एसीएमओ डॉ. हेमन्त मलिक सहित अन्य

जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और नगर निकायों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए।

उत्तरायणी महोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। शैल सांस्कृतिक समिति पंजीकृत (शैल परिषद) के तत्वाधान में आगामी 13 और 14 जनवरी को शैल भवन में आयोजित होने वाले उत्तरायणी महोत्सव की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। महोत्सव को भव्य रूप देने के लिए समिति के पदाधिकारियों ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें अंतिम रूप दिया। इस महोत्सव को लेकर प्रवासियों और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शैल परिषद के संरक्षक डॉक्टर केंसी चंदौला ने बताया कि दो दिवसीय महोत्सव को दिव्य और स्मरणीय बनाने के लिए विशेष रूपरेखा तैयार की गई है। महोत्सव के प्रथम दिन, 13 जनवरी को लोक कलाकारों द्वारा

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिसमें उत्तराखंड के विख्यात लोक गायक गजेंद्र राणा और लोक गायिका डॉक्टर कुसुम भट्ट अपनी



आवाज का जादू बिखेरेंगे। इनके साथ ही विक्रम रावत, जगदीश भट्ट, राजेंद्र बिष्ट, साक्षी काला, पवन रावत, पंकज बणई, शिवम शर्मा सहित अन्य कलाकारों द्वारा

कुमाऊं और गढ़वाली संस्कृति पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। महोत्सव के दूसरे दिन, 14 जनवरी को विभिन्न विद्यालयों के बच्चों

रहेगा। इसके साथ ही परिसर में बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, विभिन्न व्यापारिक स्टॉल और पर्वतीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। खान-पान के शौकीनों के

लिए पर्वतीय स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं, जहां लोग पारंपरिक पहाड़ी खान-पान का आनंद ले सकेंगे। डॉक्टर चंदौला और समिति के पदाधिकारियों ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में महोत्सव में पहुंचकर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आनंद लें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। तैयारियों का जायजा लेने के दौरान शैल सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष डी एस पटवाल, भरत लाल शाह, सतीश ध्यानी, आर एस बोरा, नरेंद्र रावत, सतीश लोहनी, दिनेश बम और मान सिंह नेगी सहित कई सदस्य मौजूद रहे।

मक्का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की नई पहल

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। जनपद में ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर मक्का उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग ने कमर कस ली है। मक्का विक्री में आने वाली सबसे बड़ी समस्या फसल में मानक से अधिक नमी होना है। निर्धारित 15 प्रतिशत के मुकाबले कटाई के समय मक्का में 25 से 30 प्रतिशत तक नमी पाई जाती है, जिसके कारण औद्योगिक इकाइयों इसे खरीदने से कतराती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर विकेश कुमार सिंह यादव ने राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान उत्तराखंड राइस मिलर्स एसोसिएशन के महासचिव अजय

बंसल और ऊधम सिंह नगर राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गगन गर्ग से चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि जनपद में वर्तमान में लगभग 300 राइस मिलर्स संचालित हैं और सभी के पास ड्रायर की सुविधा उपलब्ध है। मिलर्स ने प्रशासन के इस प्रयास में सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही यह सुझाव भी दिया गया कि जनपद की इकाइयों के अलावा उत्तर प्रदेश की निकटवर्ती औद्योगिक इकाइयों से भी मक्का क्रय करने का अनुरोध किया जाए। इसी क्रम में शाहजहांपुर स्थित तिलहर के एथेनॉल प्लांट संचालक रिषभ बंसल से भी संपर्क किया गया, जिन्होंने ऊधम सिंह नगर से मक्का खरीदने पर सहमति जताई है। मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि बैठक बेहद सकारात्मक रही है और इस वर्ष मक्का विक्रय में आने वाली बाधाओं को दूर कर लिया जाएगा।



नशा मुक्ति केंद्र में मिली भारी अनियमितताएं

बिना नवीनीकरण के चल रहे साई कृपा ट्रस्ट में गंदगी और सुविधाओं का अभाव, कार्रवाई के निर्देश

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशों और जिला न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पारुल थपलियाल ने प्रशासनिक टीम के साथ कमलावागांजा स्थित साई कृपा ट्रस्ट पुनर्वास एवं नशा मुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्र में भारी अनियमितताएं और अव्यवस्थाएं

पाई गईं, जिस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों को नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण टीम में उप जिलाधिकारी नवाजिश खलिक, चिकित्सा विभाग से एसीएमओ डॉक्टर श्वेता भंडारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि संस्था का वैध नवीनीकरण नहीं कराया गया है और बिना अनुमति के ही केंद्र का संचालन किया

जा रहा है। इसके अतिरिक्त परिसर में साफ-सफाई की स्थिति अत्यंत दयनीय मिली और कमरों में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था का भी अभाव पाया गया। टीम के अनुसार ऐसी स्थितियों में वहां रह रहे रोगियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 की धारा 65 और राज्य मानसिक स्वास्थ्य नियमावली 2023

की धारा 12 में दी गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव और नियमों की अनदेखी के चलते साई कृपा ट्रस्ट के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अन्य निजी पुनर्वास केंद्रों में भी हड़कंप मचा हुआ है।



SAHAS HOMEO साहस होम्यो मेडिकल स्टोर एवं क्लीनिक

जर्मन तथा सभी प्रकार के होम्योपैथिक व बायोकेमिक सप्लायर्स को विक्रेता

डॉ. यश पाण्डेय
होम्योपैथिक फिजिशियन
बी.एच.एम.एस., जयपुर

चर्म रोग | गुदा रोग | पेट रोग
गुवा रोग | लिंवर सम्बन्धि रोग

अन्य रोग • स्पान्डीलाइटिस • श्वास रोग • मोटापा • दमा
• प्रोस्टेट • माइग्रेन • टाबिसिस • एलर्जी • ब्रोनकाइटिस
बच्चों के रोग • पेट का दर्द • अपच • कान में संक्रमण / दर्द • खांसी
• जुकाम • निमोनिया • बुखार • दांत निकलना

साहस होम्यो क्लीनिक
निकट गुरुद्वारा, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी
मो. 9456727473, 9410514531 | राबितार अंतकाश

मोदी मैदान में खेल स्टेडियम बनाने की कवायद शुरू

विधायक शिव अरोरा के प्रयासों से इसी माह निकलेगा 20 करोड़ के पहले चरण का टेंडर

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। रुद्रपुर के युवाओं के लिए नए साल का आगाज एक बड़ी सौगात के साथ हुआ है। शहर के बहुप्रतीक्षित खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य अब धरातल पर उतरने जा रहा है। विधायक शिव अरोरा ने बुधवार को जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मोदी मैदान में बनने वाले इनडोर-आउटडोर स्टेडियम के फाइनल डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद विधायक ने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि जनवरी माह में ही स्टेडियम निर्माण के पहले चरण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विधायक शिव अरोरा ने बताया कि वर्ष 2022 के चुनावी संकल्प को पूरा करने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम है। उन्होंने 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मोदी मैदान में स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता देते हुए अपनी घोषणाओं में शामिल किया। इसके बाद मई 2024 में



प्रशासन द्वारा 20 एकड़ भूमि जिला विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी गई थी। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री की विकासोन्मुख सोच के कारण ही रुद्रपुर को इतनी बड़ी सौगात मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जनप्रतिनिधि केवल घोषणाएं करते थे, लेकिन अब कार्य धरातल पर नजर आ रहा है। जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जयकिशन ने बैठक में जानकारी दी कि स्टेडियम का निर्माण

चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले चरण के लिए डिजाइन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो चुकी है, जिस पर लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस चरण में मैदान की चारों ओर सुरक्षा दीवार (बाउंड्रीवॉल), भव्य प्रवेश द्वार, साइकिल ट्रैक, ओपन एम्फीथिएटर, बच्चों के लिए विशेष खेल ब्लॉक और मैदान का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा दर्शकों और खिलाड़ियों

की सुविधा के लिए 500 वाहनों की क्षमता वाली बड़ी पार्किंग का निर्माण भी पहले ही चरण में होगा। स्टेडियम के दूसरे चरण में खेल सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जाएगा। इसमें दर्शकों के बैठने के लिए आधुनिक दीर्घा के साथ-साथ वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों के लिए अलग-अलग ब्लॉक तैयार किए जाएंगे। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि खेल गतिविधियों के लिए युवाओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और स्टेडियम के रखरखाव की जिम्मेदारी स्वयं जिला विकास प्राधिकरण संभालेगा। विधायक शिव अरोरा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस स्टेडियम से स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी खेल क्षमता निखारने का बेहतर अवसर मिलेगा। बैठक के दौरान पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता नरेंद्र नवानी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

तह बाजारी मार्ग पर नाली की टूटी जाली बनी मुसीबत

दिनेशपुर (उद संवाददाता)। दुर्गा मंदिर से तह बाजार की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर सड़क के बीचों-बीच बना गड्ढा राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जर्जर हो चुकी नाली के ऊपर लगी लोहे की जाली पूरी तरह गलकर क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके चलते यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय नगर पंचायत प्रशासन की ओर से इस दिशा में अब तक कोई ठोस मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिससे स्थिति और भी विकट होती जा रही है। इस व्यस्त मार्ग पर आवागमन



करने वाले राहगीर हर समय डर के साये में रहते हैं। बुधवार सुबह उर्मिला देवी इस गड्ढे की चपेट में आने से चोटिल हो गईं। सब्जी यूनियन से जुड़े निमाई के अनुसार इस मार्ग पर तड़के से ही वाहनों का परिचालन शुरू हो जाता है। सब्जी विक्रेता और मछली व्यापारी मंडी जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। शनिवार को लगने वाले हाट बाजार के दिन यहां भीड़ अधिक होने के कारण समस्या और भी बढ़ जाती है। सड़क किनारे रहने वाले निवासियों का कहना है कि नगर पंचायत के पदाधिकारियों को इस समस्या की पूरी जानकारी है, लेकिन समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी मोहम्मद यामीन का कहना है कि समस्या उनके संज्ञान में है और जल्द ही क्षतिग्रस्त जाली की मरम्मत करवा दी जाएगी।

अतिक्रमण हटाकर किया चालान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिले बलराज पासी और पाण्डे

हल्द्वानी। प्रशासनिक व नगर निगम अधिकारियों की अगुवाई में बुधवार को नगर के अनेक बाजारों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिससे अतिक्रमणकारी दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। टीम द्वारा मुख्य रूप से सबसे व्यस्त



रहने वाले बाजारों सदर बाजार, कारखाना बाजार, एवं कालादूंगी रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। जिसमें 14500 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई। इसके साथ ही दो ट्राली सामान भी जब्त किया गया। अभियान में नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी, मुख्य नगर आयुक्त एवं नगर निगम की टीम शामिल थी।

नियम विरुद्ध चल रहे 17 ई-रिक्शा सीज

हल्द्वानी। परिवहन विभाग के प्रवर्तन दलों ने कुमाऊं मंडल आयुक्त के निर्देशों का अनुपालन करते हुए शहर के विभिन्न मार्गों पर रात्रि चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान मुख्य रूप से उन ई-रिक्शा चालकों के विरुद्ध संचालित किया गया, जो रात के समय लाइट बंद करके वाहन चलाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। कार्रवाई के दौरान नियम विरुद्ध संचालन करने पर 17 ई-रिक्शा सीज कर दिए गए। इंटरसेप्टर प्रभारी पवन कुमार और परिवहन कर अधिकारी जगदीश चंद्र के नेतृत्व में विशेष चेकिंग अभियान हल्द्वानी - नैनीताल रोड और हल्द्वानी- कालादूंगी रोड पर चलाया गया। चेकिंग के दौरान ई-रिक्शा की हेडलाइट, रिफ्लेक्टर और आवश्यक प्रपत्रों की गहनता से जांच की



गई। प्रवर्तन दल ने बिना लाइट के वाहन चलाने और यातायात नियमों की अनदेखी करने पर 25 वाहनों के चालान किए, जबकि गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 17 ई-रिक्शा को मौके पर ही सीज कर दिया गया। इस अभियान में सहायक उप निरीक्षक आरसी पवार, गिरीश कांडपाल

सहित परिवहन पर्यवेक्षक चंदन सप्याल, अरविंद कुमार, रोहित, विनय कुमार और सुनील आदि शामिल रहे। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह के चेकिंग अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

वन दरोगा बनी अनाथ विशाखा दिवाकर को डीएम ने किया सम्मानित

रुद्रपुर। उत्तराखंड सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए लागू किए गए क्षैतिज आरक्षण के तहत जनपद की प्रथम बालिका विशाखा दिवाकर का चयन वन दरोगा के पद पर हुआ है। बाजपुर के बन्नाखड़ा निवासी विशाखा की इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कैंप कार्यालय में उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जिलाधिकारी ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों और अनेक कठिनाइयों से गुजरते हुए परिश्रम के बल पर यह मुकाम हासिल करना पूरे जनपद के लिए गर्व की बात है। जिलाधिकारी ने अन्य बच्चों का आह्वान करते हुए कहा कि वे विशाखा



से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। उन्होंने जोर दिया कि ईमानदारी और लगन से किया गया कार्य किसी भी व्यक्ति को सफलता के शीर्ष तक पहुंचा सकता है। सरकार असाहाय बच्चों की शिक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके तहत

जनपद में कोचिंग सेंटर और पुस्तकालयों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि ऐसे प्रतिभावान बच्चों को चिन्हित कर प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। सम्मानित

केंद्रीय मुख्यालय में हुई शिष्टाचार भेंट, संगठन और राजनीति पर हुई चर्चा



नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से बुधवार को पूर्व सांसद बलराज पासी और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने भाजपा केंद्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान प्रदेश के राजनीतिक एवं संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने श्री नबीन को राष्ट्रीय स्तर पर मिले इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि श्री नबीन की यह नियुक्ति उनके दीर्घ संगठनात्मक अनुभव, कुशल नेतृत्व क्षमता, सक्रिय जनसंपर्क तथा पार्टी के प्रति समर्पित कार्यशैली का प्रत्यक्ष

प्रमाण है। पूर्व सांसद बलराज पासी एवं विधायक अरविंद पांडे ने आशा व्यक्त की कि श्री नबीन के नेतृत्व में संगठन और अधिक गतिशील, अनुशासित और सशक्त बनेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की मूल विचारधारा- "राष्ट्र प्रथम, संगठन सर्वोपरि"-को देशभर में और तीव्रता से आगे बढ़ाने में श्री नबीन की

भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। श्री पासी और पांडे का कहना था कि पार्टी संगठन सेवा, समर्पण, कार्यकुशलता और अनुशासन के बल पर निरंतर विस्तार और मजबूती की ओर बढ़ रहा है। नितिन नबीन के मार्गदर्शन में संगठनात्मक कार्य न सिर्फ अधिक प्रभावी होंगे, बल्कि जमीनी स्तर तक परिणामकारी प्रभाव भी दिखाएंगे। भेंट के दौरान क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर भी सार्थक संवाद हुआ। इस अवसर पर सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे, जिन्होंने नितिन नबीन को शुभकामनाएं दीं तथा उनकी नियुक्ति को संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम बताया।

प्रदेश संयोजक बनने पर राठौर का जोरदार स्वागत

किच्छा। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और ओबीसी मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीकांत राठौर को संगठन द्वारा प्रदेश स्तर की बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद नगर में उनके स्वागत का सिलसिला तेज हो गया है। श्रीकांत राठौर को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा उत्तराखंड का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। इस उपलब्धि पर किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत श्री बालाजी पुरम में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण के साथ उनका जोरदार अभिनंदन किया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त प्रदेश संयोजक को बड़ी माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्रीकांत राठौर ने कहा कि भारतीय जनता



पार्टी ही सतत विकास की राह पर ले जाने वाली एकमात्र पार्टी है। उन्होंने कहा कि देश से लेकर प्रदेश तक विकास की गाथा केवल भाजपा द्वारा ही लिखी गई है। केंद्रीय और राज्य नेतृत्व के मार्गदर्शन में आज जनमानस का उत्थान हो रहा है। उन्होंने विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग के लोगों से पार्टी के साथ जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग का हित भाजपा में ही सुरक्षित है। आगामी राजनीतिक लक्ष्यों पर चर्चा करते हुए राठौर ने कार्यकर्ताओं को 2026 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कसने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रूप में राज्य को एक युवा और विजयनी नेतृत्व मिला है, जिनके प्रयासों से उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कार्यक्रम का संचालन विशाल शर्मा ने किया। इस दौरान अरविंद शर्मा, विजय राठौर, सपना, सीमा, गंगा देवी, करण, अर्जुन, प्रमोद, शंकर राठौड़, महेंद्र कश्यप, अनिल कश्यप, सनी छाबड़ा, उमेश कश्यप, अजय राठौर, गुड्डू राठौर, आनंद, संदीप आर्य, शांति देवी, ख्यालीराम कश्यप, प्रिंस सिंह, मोहित, हरीश और रोहित सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

डाक्टर के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा

खटीमा (उद संवाददाता)। लखनऊ के केंजीएमयू में महिला डॉक्टर से शादी का झांसा देकर यौन शोषण और गर्भपात कराने के आरोपी डॉक्टर के खटीमा वार्ड नंबर 14 स्थित घर पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। आरोपी डॉ. रमीजुद्दीन पर यौन शोषण और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। लखनऊ में उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच में जुटी पुलिस को जब पता चला कि आरोपी डॉक्टर का घर खटीमा में है तो उसकी तलाश में कई बार दबिश दी लेकिन उसके वार्ड नंबर 14 खटीमा स्थित घर पर ताला लटका मिला। बुधवार को लखनऊ चौक कोतवाली पुलिस के दरोगा विक्रांत सिंघाल और आरक्षी विक्रम सिंह ने दबिश के बाद न्यायालय के आदेश पर उसके घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया।

उत्तरांचल दर्पण

सम्पादकीय

सत्यम् शिवम् सुन्दरम्



हिंसक विरोध प्रदर्शन

अगर कोई व्यक्ति या समूह किसी बात से सहमत नहीं है, तो वह अपना विरोध प्रकट कर सकता है। मगर इसका तरीका कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण और अहिंसक होना चाहिए। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन यह अधिकार कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में एक धार्मिक स्थल के निकट बुधवार तड़के अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान पथराव की घटना गंभीर चिंता पैदा करती है, जिसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। सवाल है कि विरोध प्रदर्शन हिंसक कैसे हो गया? क्या वजह रही कि लोगों ने पुलिस कार्रवाई को रोकने के लिए ईट-पत्थरों का सहारा लिया? दरअसल, सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों ने इस घटना को हिंसक रूप दे दिया, जिसमें दावा किया गया कि अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान एक धार्मिक स्थल को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और पुलिस बल पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। गौरतलब है कि पत्थरबाजी की घटनाएं पहले कश्मीर में आए दिन देखी जाती थीं। कई बार तो आतंकीयों को बचाने के लिए भी सुरक्षाबलों पर पथराव किया जाता था। यहां तक कि मुठभेड़ के दौरान भी सुरक्षा कर्मियों को रोकने के लिए पत्थरबाजी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि, सरकार और प्रशासन की सख्ती से हाल के वर्षों में घाटी में इस तरह की घटनाएं काफी कम हो गई हैं। मगर, विरोध प्रदर्शन के नाम पर इसी तरह के कृत्य अब दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा का प्रकरण भी काफी चर्चा में रहा है, जिसमें पुलिस बल पर जमकर पथराव किया गया था। अब दिल्ली में इसी तरह की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर भी नए सिरे से बहस जोर पकड़ने लगी है। यह अक्सर देखा गया है कि इस तरह के मामलों में लोगों को एक जगह एकत्रित करने और उन्हें हिंसा के लिए उकसाने में सोशल मीडिया पर अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं का सहारा लिया जाता है। पुलिस के मुताबिक, अदालत ने रामलीला मैदान इलाके में एक धार्मिक स्थल के निकट स्थित औषधालय सहित कुछ व्यावसायिक ढांचों को अतिक्रमण घोषित किया था और इसे हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम के कर्मी पुलिस बल के साथ मौके पर गए थे। इसी बीच, सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी गई कि इलाके में स्थित धार्मिक स्थल को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल है कि जब अदालत ने इन व्यावसायिक ढांचों को अतिक्रमण करार दिया था, तो लोग बिना सोचे-समझे इतने आक्रामक कैसे हो गए? जबकि जिस धार्मिक संरचना को गिराने की अफवाह फैलाई गई, वह पुलिस कार्रवाई का हिस्सा थी ही नहीं। पुलिस अब इस बात की जांच भी कर रही है कि पथराव की यह घटना अचानक हुई या फिर किसी पूर्व नियोजित साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया। यह आशंका इसलिए भी जताई जा रही है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई अदालत के फैसले के बाद की गई और अगर स्थानीय लोगों को कोई आपत्ति थी, तो वे समय रहते ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे। इस घटना में जो भी दोषी हैं, उन्हें न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए।

हिमालयी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सैन्य और नागरिक समन्वय अनिवार्य

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सामरिक मजबूती के लिए साझा दृष्टिकोण पर दिया जोर

देहरादून (उद संवाददाता)। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) द्वारा आज क्लेमेंट टाउन, देहरादून में "फोर्टिफाइंग द हिमालयाज: ए प्रोएक्टिव मिलिट्री-सिविल-सोसाइटी एंजिनियरिंग इन द मिडिल सेक्टर" विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में प्रतिभाग किया गया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि हिमालय केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि एक जीवंत रणनीतिक प्रणाली है, जहाँ भू-आकृति,

से नहीं, बल्कि नागरिक प्रशासन, स्थानीय समुदायों और प्रौद्योगिकी के साथ प्रभावी समन्वय से सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने सीमावर्ती गांवों को राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण घटक बताते हुए कहा कि स्थानीय समुदाय केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि सीमाई सुरक्षा के सहभागी और बलवर्धक हैं। उन्होंने कहा कि 'वाइब्रेंट विलेज' जैसे कार्यक्रम सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ जनसंख्या स्थिरता, लॉजिस्टिक मजबूती

हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन का सीधा संबंध परिचालन क्षमता से है। पर्यावरणीय क्षरण से न केवल जीवन और आजीविका प्रभावित होती है, बल्कि लॉजिस्टिक्स, संचार और आपदा प्रबंधन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच संतुलित दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। अपने संबोधन के समापन पर राज्यपाल ने कहा कि हिमालयी सीमाओं की वास्तविक

होना आवश्यक है। हिमालयी क्षेत्रों में सीमाओं के आस-पास निवास करने वाले नागरिक देश की सबसे बड़ी शक्ति है, जो वास्तव में देश के आँख और कान बनकर राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम योगदान निभाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा करना सेना के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की



आधारभूत संरचना, जनसंख्या, शासन और सैन्य क्षमता निरंतर परस्पर क्रिया में रहती हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि मध्य सेक्टर को परंपरागत रूप से अपेक्षाकृत शांत माना जाता रहा है, किंतु वर्तमान परिस्थितियाँ सतत सतर्कता और पूर्व तैयारी की मांग करती हैं। उन्होंने हिमालयी क्षेत्र, विशेष रूप से भारत-चीन सीमा के मध्य सेक्टर में, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सैन्य, नागरिक प्रशासन और समाज के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि समकालीन सुरक्षा चुनौतियाँ अब केवल प्रत्यक्ष सैन्य गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हाइब्रिड वारफेयर, ग्रे-जोन गतिविधियों, द्वि-उपयोगी आधारभूत संरचना, और सीमा क्षेत्रों में निरंतर दबाव जैसे कारकों से भी आकार ले रही हैं। ऐसे परिदृश्य में हिमालयी क्षेत्रों की दीर्घकालिक सुरक्षा केवल सैन्य तैयारियों

और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थायी राष्ट्रीय उपस्थिति को भी सुदृढ़ करते हैं। राज्यपाल ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सड़कें, सुरंगें, पुल, हवाई संपर्क और दूरसंचार सुविधाएँ परिचालन तत्परता के अनिवार्य घटक हैं। उन्होंने चारधाम परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह न केवल तीर्थाटन और आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाती है, बल्कि रणनीतिक गतिशीलता और सुरक्षा तैयारियों को भी मजबूती प्रदान करती है। उन्होंने आधुनिक प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ड्रोन, उन्नत निगरानी प्रणालियाँ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म परिस्थितिजन्य जागरूकता और त्वरित प्रतिक्रिया में सहायक हैं, किंतु तकनीक नेतृत्व, विवेक और संस्थागत मजबूती का विकल्प नहीं हो सकती। राज्यपाल ने यह भी कहा कि

शक्ति शांत तैयारी, संस्थागत समन्वय और सामाजिक विश्वास में निहित है। जब सैन्य बल, नागरिक प्रशासन और समाज एकजुट होकर कार्य करते हैं, तब हिमालयी सीमाएँ अधिक सुदृढ़, स्थिर और सुरक्षित बनती हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण तथा सैन्य नागरिक से जुड़े विषय पर सेमिनार का होना अति महत्वपूर्ण है। कहा कि सेमिनार से निकले सुझाव हमारी सामरिक नीति को सुदृढ़ बनाने में सहायक एवं हिमालयी क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित जनसंख्या जैसी चुनौतियों को देखते हुए सेना, नागरिकों, सिविल प्रशासन और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच बेहतर समन्वय

दिशा में कार्य किया जा रहा है। कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीमांत गांव माणा जैसे दूरस्थ और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने ही माणा को देश के अंतिम गांव की जगह देश के प्रथम गांव बताया था। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। जीओसी-इन-सी, सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेनगुप्ता ने मध्य क्षेत्र के बॉर्डर की चुनौतियों, नागरिक समाज के सशक्तीकरण और तकनीक के अपग्रेडेशन के साथ ही अवसरचतानात्मक विकास के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राजदूत अशोक के. कांथा (सेवानिवृत्त), ब्रिगेडियर अंशुमान नारंग (सेवानिवृत्त), लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) सहित संबंधित उपस्थित थे।

अमेरिका की बेलगामी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की लाचारी

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सेलिया फ्लोरेस का अमेरिका द्वारा किए गए अपहरण और गिरफ्तारी ने महाकवि तुलसीदास की इस कहावत 'समर्थ को नहीं दोष गुसाई' को चरितार्थ कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहे जिन कुतर्कों को तर्क बताकर अपने हठ को सच बताते रहें, वास्तविकता यही है कि इस कार्यवाही को किसी भी कानून के परिप्रेक्ष्य में तर्कसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है? वेनेजुएला के पक्ष में आवाज उठाने वाले दक्षिण अमेरिकी देश कोलांबिया के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की आपात बैठक भी हुई, जिसमें अमेरिका ने अपना पक्ष रखा और अपने तानाशाही रवैये को जायज ठहराया। हालांकि चीन ने अमेरिका की इस सैन्य कार्यवाही को सीधे-सीधे दादागिरी बताया। रूस ने भी आपाति जताई है। लेकिन बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताने के अलावा अमेरिका के विरुद्ध कोई भी कड़ी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य में लाचार नजर आए। गुटेरस ने कहा कि यह सैन्य कार्यवाही क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रभुत्व के लिए चेतावनी है। इस कार्यवाही में अंतरराष्ट्रीय कानूनों और नियमों का पालन नहीं किया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता एवं राजनीतिक

स्वतंत्रता के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किंतु इसकी अनदेखी की गई। वेनेजुएला के प्रतिनिधि ने अमेरिका द्वारा किए गए हमले को अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों और तेल को प्राप्त करना बताया। ऐसी ही निंदा रूस, चीन, मैक्सिको, क्यूबा और कई देशों ने अमेरिका की कड़ी आलोचना की, किंतु अमेरिका के मित्र देश उसके साथ खड़े दिखाई दिए हैं। दुनिया के तेल भंडार का 18.17 प्रतिशत तेल अर्थात् 303 अरब बैरल तेल और दुर्लभ खनिज के भंडार वेनेजुएला की धरती में समाए हुए हैं। किंतु उसके पास कच्चे तेल को घोधन करने के तकनीकी संसाधन नहीं हैं। इसलिए इस तेल को ईंधन में नहीं बदल पा रहा है। इस तेल को घोधन के लिए जब मादुरो ने चीन से तेल और रूस से हथियार खरीदने की नीति को अंजाम दिया तो ट्रंप की नाराजी बढ़ गई और मादुरो और उनकी पत्नी सेलिया का अपहरण कर लिया। इस अपहरण को घटनाक्रम को लेकर मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा ने कहा है कि इतिहास बताएगा कि हमारे भीतर के लोगों ने किस तरह से गद्दारी करते यह राष्ट्रघात किया? मीडिया द्वारा ऐसी जानकारियां सामने लाई गई हैं कि वेनेजुएला सरकार में काम कर रहे लोगों ने ही उपहारों के लालच में आकर अमेरिकी सेना को राष्ट्रपति मादुरो के आवास तक पहुंचाने में मदद की है। हालांकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर

अमेरिका में मानक पदार्थों की तस्करी अमेरिका में करने का हवाला देकर इस सैन्य कार्यवाही को जायज ठहराया है। मादुरो को अमेरिकी कानून के-फ्रिस्बी के तहत पकड़ा गया है। यह कानून अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद-2 के तहत राष्ट्रपति को गैर-कानूनी तरीकों से ऐसे लोगों और भागोड़ों को पकड़ने की अनुमति देता है, जो अमेरिका को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हों। इसमें प्रावधान है कि गिरफ्तारी का तरीका कितना भी गैर-कानूनी हो, एक बार अमेरिका में लाने के बाद अमेरिकी अदालत में मामला चलाया जा सकता है। इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। मादुरो पर मादक पदार्थ तस्करी के अपराधिक मामले अमेरिका में दर्ज हैं। इनमें कम से कम 20 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है। अमेरिका ऐसा दुस्साहस 1990 में पनामा के तानाशाह मैनुअल नोरिएगा को गिरफ्तार करके दिखा चुका है। इन्हें अमेरिकी अदालत ने 40 साल की सजा सुनाई थी, किंतु 2011 में रिहा कर दिया गया था। यदि मादुरो को सजा सुनाई जाती है तो ट्रंप के राष्ट्रपति नहीं रहने के बाद कोई दूसरा राष्ट्रपति मादुरो को क्षमादान दे सकता है। खुद ट्रंप होडुगस के पूर्व राष्ट्रपति हर्नान्डेज को 2025 में माफी दे चुके हैं। अमेरिका कभी मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी का बहाना ढूँढ़कर अपने षत्रु राष्ट्रों के मुखियाओं को सबक सिखाता रहा है।

2003 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश सरकार ने ईराक पर जैविक और रासायनिक हथियार होने का दावा कर ईराक को नेस्तनाबूद कर दिया था। वहां के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को भी अपदस्थ कर दिया था। इसी तरह 2011 में अमेरिका और नाटो ने लीबिया और सीरिया में भी सैन्य हस्तक्षेप कर वहां की वर्तमान सरकारों को अपदस्थ कर दिया था। इन हस्तक्षेपों के चलते आज भी इन देशों में गृहयुद्ध एवं अस्थिरता के हालात बने हुए हैं। यही हथ्र अब वेनेजुएला का होना निश्चित है। अमेरिका के सरकारी शोध संस्थान कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार 1798 से लेकर अब तक अमेरिका 469 सैन्य हस्तक्षेप दुनिया में इसलिए कर चुका है, जिससे उसे महाशक्ति माना जाता रहे। दुनिया में लगातार ऐसे हालातों की निर्मित सामने आने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र की कार्य-संस्कृति लाचार बनी हुई है। उस पर निरंतर प्रश्न-चिन्ह उठ रहे हैं। अतएव यदि यह वैश्विक संस्था अपने भीतर समयानुकूल सुधार नहीं लाती है तो कालांतर में महत्वहीन होती चली जाएगी और फिर इसके सदस्य देशों को इसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। भारत जैसे देश को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता से बाहर रखते हुए इस संस्था ने जता दिया है कि वहां चंद अलोकतांत्रिक या तानाशाह की भूमिका में आ चुके देशों की ही तूती बोलती है।

संयुक्त राष्ट्र की उम्र लंबी हो चुकने के बावजूद इसके मानव कल्याण से जुड़े लक्ष्य अधूरे हैं। इसकी निष्पक्षता भी संदिग्ध है। इसीलिए वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र ताकतवर देशों की मनमानी रोकने, शांति स्थापित करने और आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांतिप्रिय देशों के संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था। इसका अहम मकसद भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका और आतंकवाद से सुरक्षित रखना था। इसके सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को स्थायी सदस्यता प्राप्त है। याद रहे चीन जवाहरलाल नेहरू की अनुकंपा से ही सुरक्षा परिषद का सदस्य बना था। जबकि उस समय अमेरिका ने सुझाया था कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया जाए और भारत को सुरक्षा परिषद की सदस्यता दी जाए। लेकिन अपने उद्देश्य में परिषद को पूर्णतः सफलता नहीं मिली। भारत का ऑपरेशन सिंदूर समेत तीन बार पाकिस्तान और एक बार चीन से युद्ध हो चुका है। इराक और अफगानिस्तान, अमेरिका और रूस के जबरन दखल के चलते युद्ध की ऐसी विभीषिका के शिकार हुए कि आज तक उबर नहीं पाए हैं। रूस और यूक्रेन तथा इजराइल एवं फिलीस्तीन के बीच युद्ध एक नहीं टूटने वाली कड़ी बन गया है। अनेक इस्लामिक देश गृह-कलह से जूझ रहे हैं। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान

बेखौफ परमाणु युद्ध की धमकी देते रहते हैं। दुनिया में फैल चुके इस्लामिक आतंकवाद पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन में लगा चीन किसी वैश्विक पंचायत के आदेश को नहीं मानता। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ और शांति सेना जैसे संगठन काम करते हैं। लेकिन चंद देशों की ताकत के आगे ये संगठन नतमस्तक होते दिखाई देते हैं। इसीलिए शांति सेना की विश्व में बढ़ते सैनिक संघर्षों के बीच कोई निर्णायक भूमिका दिखाई नहीं दे रही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जरूर युद्ध में अत्याचारों से जुड़े कई दशकों पुराने अंतरराष्ट्रीय विवादों में न्याय देता दिख जाता है। परंतु संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक संगठन जी-20, जी-8, आसियान और ओपेक जैसे संगठन विभाजित दुनिया के क्रम में लाचारी का अनुभव कर रहे हैं। अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों द्वारा इन्हें दी जाने वाली आर्थिक मदद में कटौती कर दिए जाने के कारण भी इनका भविष्य संकट में है। इन सब खतरों के चलते इस वैश्विक मंच की विश्वसनीयता संकट में है, लिहाजा इसमें पर्याप्त सुधारों की तत्काल जरूरत तो है ही, वेनेजुएला के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसा करना जरूरी है, जिससे इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा के प्रति सदस्य देशों में विश्वास पैदा करे।

-प्रमोद भार्गव, लेखक/पत्रकार

सांस्कृतिक विविधता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति एआई से सशक्त होगा स्थानीय शासन 2026 बनेगा निर्णायक वर्ष: राज्यपाल

हरिद्वार में 26वें लोहड़ी महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल

हरिद्वार (उद संवाददाता)। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने हरिद्वार में पंजाबी समाज द्वारा आयोजित 26वें लोहड़ी महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व सांस्कृतिक चेतना, मांगलिक आशीर्वाद और जन-सरोकारी मूल्यों से जुड़ा हुआ है। लोहड़ी फसल उत्पादन से जुड़ा उत्सव है, जो नववर्ष के आगमन, खुशहाली और मानवता में ऊर्जा के संचार का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि लोहड़ी जैसे पर्व भारत की सांस्कृतिक विविधता में निहित एकता को दर्शाते हैं और समाज को आपसी भाईचारे, समरसता एवं बंधुत्व का संदेश देते हैं। लोहड़ी पर्व राष्ट्रीय एकता, मानव सेवा और 'विकसित भारत 2047' की भावना को सुदृढ़ करता है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसमें लोहड़ी पर्व का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि पंजाबी समाज की लोक कला, संगीत और परंपराएं विश्वभर में अद्वितीय हैं तथा कोविड-19 महामारी के



दौरान मानव सेवा में पंजाबी समाज की भूमिका सराहनीय रही है। राज्यपाल ने गुरु परंपरा के विचारों को रेखांकित करते हुए बताया कि गुरु परंपरा ने सभी मानव की उत्पत्ति एक ही पुंज से बताई, इसलिए समाज में सहिष्णुता, प्रेम और सद्भावना बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश और समाज को कल्याण हेतु कार्य करने

तथा प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने के लिए समर्पित भाव से आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर सांसद हरिद्वार क्षेत्र श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक मदन कौशिक, महापौर किरण जैसल व अनीता अग्रवाल, जिला प्रशासन एवं पुलिस अधि कारीगण, पंजाबी महासभा के पदाधिकारी तथा देश और समाज को कल्याण हेतु कार्य करने

देहरादून (उद संवाददाता)। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से बुधवार को लोक भवन में सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड श्री नितेश कुमार झा ने अपनी टीम के साथ शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उत्तराखण्ड एआई मिशन की प्रगति, वर्तमान पहलों एवं भावी कार्ययोजना पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। सचिव, आईटी विभाग ने राज्यपाल को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रभावी और चरणबद्ध उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, निर्णय-प्रक्रिया को अधिक सटीक बनाना तथा सेवाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार करना है। उन्होंने बताया कि एआई आधारित समाधान

स्थानीय शासन को सशक्त बनाने, डेटा-आधारित नीतिगत निर्णय लेने तथा नागरिक-केंद्रित सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका



निभा रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2026 को एआई क्रांति के निर्णायक वर्ष के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखण्ड के पास इस परिवर्तनकारी तकनीक के क्षेत्र में नेतृत्व करने की पूर्ण क्षमता है। राज्य की युवा प्रतिभा, शैक्षणिक

संस्थानों, तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र और प्रशासनिक इच्छाशक्ति के समन्वय से उत्तराखण्ड एआई आधारित सुशासन का एक सशक्त मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि तकनीक का उद्देश्य केवल नवाचार नहीं, बल्कि जन-कल्याण होना चाहिए। एआई का उपयोग मानवीय संवेदनाओं, नैतिक मूल्यों और पारंपरिक प्रशासनिक विवेक के साथ संतुलित रूप में किया जाना आवश्यक है, ताकि विकास समावेशी, टिकाऊ और भरोसेमंद बन सके। भेंट के दौरान भविष्य में अकादमिक संस्थानों, स्टार्ट-अप और सरकारी विभागों के बीच सहयोग को और सुदृढ़ करने, क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों को विस्तार देने तथा उत्तराखण्ड को उत्तर भारत में एआई नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर अपर सचिव आईटी एवं निदेशक आईटीडीए श्री आलोक कुमार पाण्डेय भी उपस्थित रहे।

जिले में किसान दिवस का रोस्टर तैयार कांग्रेसजनों बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा को सौंपा ज्ञापन

नैनीताल। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद अंतर्गत किसानों की विविध समस्याओं/मुद्दों के समाधान और उन्हें तकनीकी एवं वैज्ञानिक रूप से सक्षम व जागरूक बनाने हेतु प्रत्येक माह के द्वितीय बृहस्पतिवार को विकासखंडवार किसान दिवस का आयोजन किया जाएगा। 8 जनवरी को धारी में, 12 फरवरी को रामगढ़ में, 12 मार्च को रामनगर में, 9 अप्रैल को बेतालघाट में, 14 मई को ओखलाकांडा में, 11 जून को कोटाबाग में इसी क्रम में 12 जुलाई को भीमताल और 13 अगस्त, 2026 को हल्द्वानी में किसान दिवस का आयोजन किया जाएगा। किसान दिवस में कृषि क्षेत्र से जुड़े समस्त विभागों जैसे सिंचाई, ऊर्जा, समाज कल्याण, कृषि, उद्यान,

सहकारिता, मत्स्य, दुग्ध विकास, पशुपालन, गन्ना मंडी परिषद एवं रेशम विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, नाबार्ड, लीड बैंक प्रबंधक तथा इश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा। किसान दिवस आयोजन के दिन कृषकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु कृषि एवं अन्य कृषि रेखीय विभाग, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास, रेशम भेषज, सिंचाई, लघु सिंचाई, उद्योग, सहकारिता, ग्राम विकास, रीप, नाबार्ड बैंक, कृषि विज्ञान केंद्र, प्वात संस्थान, गन्ना मंडी परिषद, इफको, नाबार्ड एवं बैंक आदि सभी अपने सुसज्जित विभागीय स्टॉल भी लगाएंगे। इस अवसर पर किसान अपने-अपने गांव की समस्याओं को बैठक में रखेंगे, तथा

उन समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित कृषकों को विभागों की योजनाओं, सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त रासायनिक/उर्वरकों, कीटनाशकों, तकनीकी ज्ञान, बीज, खाद, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, किसान पेंशन आदि अन्य योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। प्राकृतिक एवं जैविक खेती के प्रचार प्रसार एवं इसे अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। एकीकृत कृषि और सह-फसली खेती पर विशेष बल दिया जाएगा। किसान दिवस में प्राप्त समस्याओं एवं उनके समाधान इत्यादि के विवरण सहायक कृषि अधिकारी संकलित कर मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल को ईमेल, सॉफ्टवेयर या हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराया जाएगा।

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों एवं हत्याओं को अविलंब रोकने के लिए कांग्रेसजनों ने उपजिलाधिकारी को माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। जिसमें इस मामले में भारत सरकार द्वारा शीघ्र एवं ठोस कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट के पश्चात उत्पन्न अराजक परिस्थितियों के चलते वहाँ हिंदू समुदाय सहित अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध असामाजिक एवं अराजक तत्वों द्वारा निरंतर हिंसक घटनाएँ की जा रही हैं। हिंदू समुदाय को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जो अत्यंत निंदनीय, अमानवीय तथा लोकतांत्रिक एवं मानवीय मूल्यों के सर्वथा विपरीत है। बांग्लादेश में उत्पन्न

इन् गंभीर हालातों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वहाँ के हिंदुओं एवं समस्त अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रही हिंसक घटनाओं को अविलंब रोका जाए तथा

संरक्षण की ठोस मांग की जाए। इस दौरान महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट, जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल, हरीश मेहता, सतीश नैनवाल, जिलाध्यक्ष



शांति, सुरक्षा एवं मानवाधिकारों की बहाली हेतु प्रभावी, ठोस एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा गंभीरता से उठाते हुये पीड़ित हिन्दू समुदाय की सुरक्षा एवं

महिला कांग्रेस खप्टी बिष्ट, महानगर महिला अध्यक्ष मधु सांगुड़ी, नीमा भट्ट, जया कर्नाटक, शोभा बिष्ट, भागीरथी बिष्ट, ब्लॉक अध्यक्ष मोहन बिष्ट, जाकिर हुसैन, मलय बिष्ट, पार्षद मुकुल बलुटिया, हेमन्त शर्मा, महेशानंद, राजेन्द्र जीना, मयंक भट्ट, योगेश जोशी, राजेन्द्र बिष्ट, प्रदीप नेगी, राजू सुयाल आदि मौजूद थे।

पेज एक का शेष...

रुद्रपुर में फिर गरजा... विस्तार किया जा रहा है। टीम के साथ कोतवाल मनोज रतूडी और ट्रांजिट कैम्प कोतवाली प्रभारी मनोज पाण्डे भारी पुलिस फोर्स के साथ मुस्तैद रहे। कार्रवाई शुरू होते ही बाबा बालक राम ने टीम का रास्ता रोकने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तुरंत हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचते ही सबसे पहले अवैध रूप से डाली गई झोपड़ियों को खाली कराया। बाबा का सारा सामान सुरक्षित निकालकर निगम ने अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद दो मशीनों ने अतिक्रमण को दहाना शुरू किया। देखते ही देखते सालों पुराना अवैध कब्जा साफ हो गया। इसके तुरंत बाद नगर आयुक्त ने भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घेराबंदी के निर्देश दिए। निगम के कर्मचारियों ने आनन-फानन में टीन शेड लगाकर 6 एकड़ भूमि की हदबंदी कर दी और वहां सरकारी स्वामित्व का बोर्ड लगा दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर गंगापुर मुख्य मार्ग से शैलजा फार्म की ओर आने वाले सभी संपर्क मार्गों को रस्सी लगाकर बंद कर दिया गया था। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद या झूठे आरोपों से बचने के लिए नगर निगम ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया। पूरी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई और ड्रोन कैमरों से पूरे भूखंड की मैपिंग की गई। अधिकारियों का कहना है कि यह जमीन अब नगर निगम के सुरक्षित डेटाबेस में शामिल है और इसका उपयोग भविष्य में जनहित की बड़ी योजनाओं के लिए किया जाएगा।

राइस मिल ने डकारा... बातों से मुकर गया। मिल द्वारा जमानत के तौर पर दिए गए चेकों को लेकर भी उनके अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा गया कि उन्हें बैंक में प्रस्तुत न किया जाए, जिससे साफ जाहिर होता है कि खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं थी और चेक केवल कार्रवाई टालने के लिए दिए गए थे। पीसीयू द्वारा 10 जुलाई 2025 तक भुगतान का अंतिम अवसर देने के बाद भी जब 98,47,788 रुपये की रिकवरी नहीं हुई, तो विभाग ने कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया। पुलिस ने मिल के निदेशक पुरुषोत्तम दास, निदेशक लक्ष्मी अग्रवाल और लेखाकार राजेंद्र सिंह के विरुद्ध षडयंत्र के तहत सरकारी संपत्ति का गबन करने और धोखाधड़ी का अभियोग पंजीकृत किया है। पुलिस अब मिल के वित्तीय लेन-देन और अन्य संपत्तियों की जांच कर रही है। **आस्था के नाम पर**... यह सख्त कदम उठाना पड़ा। महापौर ने कहा कि पिछले दिनों कुछ लोग नगर निगम की कार्यवाही को धर्म विशेष के विरुद्ध बता रहे थे। नगर निगम ने खेड़ा में ईदगाह की आड़ में कब्जाई गई करोड़ों की भूमि मुक्त कराई गई थी और किच्छा रोड पर भी मंदिर की आड़ में किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया था। आज की कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि नगर निगम का अभियान निष्पक्ष और पारदर्शी है। निगम का उद्देश्य किसी धर्म को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकारी संपत्तियों को भू-माफियाओं के चंगुल से छुड़ाना है। महापौर ने कहा कि अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध यह अभियान भविष्य में भी इसी तीव्रता के साथ जारी रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुक्त कराई गई भूमि की उचित घेराबंदी की जाए ताकि भविष्य में दोबारा कब्जा न हो सके। इस भूमि का उपयोग भविष्य में जनहितकारी योजनाओं के लिए किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

ठंड से बचने.... सूखी लकड़ियों और झाड़ियों को इकट्ठा कर तीन अलग-अलग स्थानों पर अलाव जलाए। ड्यूटी पर तैनात जवान और कर्मचारी बारी-बारी से आग की तपिश लेकर खुद को गर्म रखते रहे और ऑपरेशन जारी रखा। **बेसुध गाय के**... प्रबंध किया। निगम के दर्जनों कर्मचारियों ने मिलकर बेसुध गाय को बड़े जतन से ट्रैली में लिये और बछड़ों के साथ सुरक्षित गौशाला भिजवाया, जहां उनके उपचार और चारे की व्यवस्था की गई।

अल्मोड़ा (उद संवाददाता)। सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी से परेशानी झेल रहे मरीजों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में तैनात 40 से अधिक डाक्टर विशेषज्ञ बनने के लिए जाएंगे। ऐसे में खासकर दूरस्थ क्षेत्र के मरीजों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जिला मुख्यालय स्थित अस्पतालों समेत सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डाक्टरों का टोटा बना हुआ है। नियमित चिकित्साधि कारी के करीब 200 पद रिक्त हैं, वहीं विशेषज्ञ डाक्टरों के भी 100 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में अब जिले के सरकारी अस्पतालों में तैनात 40 डाक्टरों ने उच्च शिक्षा के लिए आवेदन किया है। आवेदनों को स्वीकृति मिलने के बाद करीब 18 डाक्टर पीजी करने के लिए चले गए हैं। जबकि अन्य डाक्टर भी शीघ्र ही पीजी करने के लिए जाएंगे।

अल्मोड़ा जिले में मरीजों की बढ़ेगी मुश्किलें

अल्मोड़ा (उद संवाददाता)। सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी से परेशानी झेल रहे मरीजों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में तैनात 40 से अधिक डाक्टर विशेषज्ञ बनने के लिए जाएंगे। ऐसे में खासकर दूरस्थ क्षेत्र के मरीजों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जिला मुख्यालय स्थित अस्पतालों समेत सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डाक्टरों का टोटा बना हुआ है। नियमित चिकित्साधि कारी के करीब 200 पद रिक्त हैं, वहीं विशेषज्ञ डाक्टरों के भी 100 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में अब जिले के सरकारी अस्पतालों में तैनात 40 डाक्टरों ने उच्च शिक्षा के लिए आवेदन किया है। आवेदनों को स्वीकृति मिलने के बाद करीब 18 डाक्टर पीजी करने के लिए चले गए हैं। जबकि अन्य डाक्टर भी शीघ्र ही पीजी करने के लिए जाएंगे।

40 से अधिक चिकित्सकों ने उच्च शिक्षा के लिए किया आवेदन



ऐसे में पहले से ही डाक्टरों की कमी से परेशान विभाग और मरीजों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। डा. नवीन चंद्र तिवार सीएमओ ने बताया कि जिले से 40 डाक्टरों ने उच्च शिक्षा के लिए आवेदन किया था। जिसमें से करीब 18 डाक्टर चले गए हैं। मरीजों को दिक्कत ना हो इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।

डिजिटल अरेस्ट कर... सारी धनराशि 'सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट' में डालनी होगी, जो जांच के बाद वापस कर दी जाएगी। अत्यधिक मानसिक दबाव और घबराहट के चलते पीड़िता ने 31 दिसंबर 2025 को अपने एचडीएफसी बैंक खाते से 1,20,18,000 (एक करोड़ बीस लाख अठारह हजार) रुपये चेक के माध्यम से टगों द्वारा बताए गए आईसीआईसीआई बैंक के खाते में स्थानांतरित कर दिए। पैसे भेजने के बाद जब उन्हें संदेह हुआ और मामले की जानकारी जुटाई, तो उन्हें अहसास हुआ कि वे साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी हैं। साइबर थाना पुलिस ने धारा 318(4) बीएनएस और 66डी आईटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस अब उन बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को खंगाल रही है, जिनके जरिए इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया।

फाइनेंस कंपनी ने...ने 26800 व 36500 रुपये, सतपाल सिंह ने 18450 व 18250 रुपये, राजेन्द्र सिंह ने 18800 रुपये व 36500 रुपये, राजेश कुमार ने 29900 व 73000 रुपये, जोशान ने 15000 व 36500 रुपये, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने 24490 रुपये, रिजवान ने 24600, राजेश कुमार ने 150000 रुपये जमा कराये हैं। इसके अलावा भी तमाम लोगों के खाते खुलवाकर धनराशि जमा करायी। आरोप लगाया कि धनराशि वापस मांगने पर एजेंट टालमटोल करता रहा। आरोप लगाया कि रकम हड़पने की मंशा है। पुलिस ने अजय गंगवार, राजेन्द्र प्रसाद, राजकुमार गंगवार, गीता देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हमारे यहां कुंडली बनाने व दिखवाने एवं वैदिक ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती पाठ महामृत्युंजय जप, गृह शांति, शतचंडी यज्ञ एवं समस्त यज्ञ जप इत्यादि समस्याओं का समाधान के लिये संपर्क करें:

आचार्य गोपाल शास्त्री जी : 7248133444

संस्थापक-स्व० हरनामदास सुखीजा एवं स्व०तिलकराज सुखीजा
स्वामित्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक परमपाल सुखीजा द्वारा उत्तरांचल दर्पण पब्लिकेशन्स, श्याम टाकीज रोड, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) से मुद्रित एवं प्रकाशित
सम्पादक- परमपाल सुखीजा
आरएनआई नं.: UTTHIN/2002/8732 समस्त विवाद रुद्रपुर न्यायालय के अधीन होंगे।
E-mail-darpan.rdr@gmail.com, www.uttaranchaldarpan.in
फोन-245886(O)245701(Fax), 9897427585, 9897427586(Mob.)

लोहड़ी पर मेयर विकास शर्मा की सराहनीय पहल

रुद्रपुर। नगर निगम के मेयर विकास शर्मा ने शहरवासियों के लिए एक अनोखी और सराहनीय पहल की है। सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे के प्रतीक लोहड़ी पर्व के अवसर पर मेयर ने घोषणा की है कि नगर निगम की ओर से लोहड़ी प्रज्वलन के लिए मुफ्त में लकड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम उत्तराखंड के किसी भी नगर निकाय क्षेत्र में पहली बार उठाया गया है, मेयर विकास शर्मा ने कहा कि लोहड़ी ऐसा त्योहार है, जिसे लोग मोहल्लों, कॉलोनियों और सामुदायिक स्थलों पर एकजुट होकर मनाते हैं। नगर निगम की यह पहल

रुद्रपुर में पहली बार लोहड़ी प्रज्वलित करने को नगर निगम कराएगा लकड़ी उपलब्ध

त्योहार को सरल और सभी के लिए सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। श्री शर्मा ने कहा कि रुद्रपुर एक ऐसा शहर है जहां सभी धर्मों और समुदायों के लोग आपस में मिलकर त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी भी ऐसा ही पर्व है, जो भाईचारे को मजबूत करता है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि जहां भी परंपरा के अनुसार लोहड़ी जलाई जाती है और लोगों को लकड़ी की जरूरत है, वे सीधे नगर निगम से संपर्क कर सकते हैं। निगम द्वारा

समय पर लकड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहल सिर्फ सुविधा 1 उपलब्ध कराने का काम नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द का संदेश देने का प्रयास है। त्योहार सबके लिए है और इसे खुशी, उमंग और एकता के साथ मनाया जाना चाहिए। मेयर विकास शर्मा ने कहा कि नगर में जहां भी सार्वजनिक रूप से लोहड़ी प्रज्वलित की जाती है, संबंधित प्रतिनिधि समय रहते नगर निगम में संपर्क कर सकता है, उनको लोहड़ी के लिए



लकड़ी उपलब्ध करा दी जाएगी। देखा जाए तो मेयर विकास शर्मा का यह प्रयास काफी सराहनीय है, क्योंकि लोहड़ी प्रज्वलन के लिए लोगों को लकड़ी एकत्र करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वास्तव में मेयर का यह फैसला जनता की जरूरतों को समझने और त्योहारों के महत्व को सम्मान देने का बेहतरीन उदाहरण है। रुद्रपुर में नगर निगम द्वारा त्योहारों पर इस तरह की पहल पहली बार की जा रही है। बल्कि पूरे उत्तराखंड में ही पहली बार रुद्रपुर में होने जा रही है और लोगों का मानना है कि इससे समाज में एकजुटता और आपसी सहयोग की भावना और मजबूत होगी।

13 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा लोहड़ी पर्व



रुद्रपुर। देश भर में 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। यह त्योहार उत्तर भारत के राज्यों, खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तराई व

मैदानी क्षेत्रों में विशेष महत्व रखता है। अब दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी लोहड़ी मनाने की परंपरा तेजी से बढ़ी है। लोग इस दिन मोहल्लों और कॉलोनियों में एकजुट हो कर

नाच-गाने और अग्नि प्रज्वलन के साथ उत्सव मनाते हैं। लोहड़ी केवल गजक, रेवड़ी और मूंगफली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक विशेष संदेश और परंपरा जुड़ी हुई है।

फसल पकने से संबंधित है लोहड़ी पर्व

लोहड़ी का मूल संबंध फसल से माना जाता है। यह पर्व नई फसल के पकने और अच्छी खेती की खुशी में मनाया जाता है। किसान सूर्य देव और अग्नि देव को धन्यवाद स्वरूप रेवड़ी और मूंगफली अर्पित करते हैं। यह त्योहार आपसी प्रेम, सद्भाव और मिलजुलकर रहने की परंपरा को भी दर्शाता है। लोहड़ी के समय फसल कटाई का समय करीब होता है, इसलिए लोग अग्नि देव के सामने प्रसाद चढ़ाकर समृद्धि की कामना करते हैं।

कौन था दुल्ला भट्टी? लोहड़ी पर क्यों किया जाता है याद

दुल्ला भट्टी मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में पंजाब का एक साहसी व्यक्ति था। कहा जाता है कि उसने अमीर सौदागरों से बेची जा रही कई लड़कियों को बचाया और उनके विवाह करवाए। उसकी बहादुरी और लोकहित के कार्यों के कारण वह पंजाब का लोकनायक माना गया। लोहड़ी पर आज भी दुल्ला भट्टी से जुड़े गीत गाकर उसकी याद को जीवित रखा जाता है। लोहड़ी का यह पर्व फसल की खुशहाली, सामाजिक एकता और लोक परंपराओं के सम्मान का प्रतीक है, जो हर साल लोगों को एकजुट होने और परम्पराओं को संजोकर रखने का संदेश देता है।

लोहड़ी पर्व के पीछे पौराणिक कथाओं का भी उल्लेख

इस पर्व का उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। मान्यता है कि राजा दक्ष द्वारा आयोजित महायज्ञ में अपमानित होने के बाद माता सती ने अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया था। लोहड़ी को माता सती की स्मृति से भी जोड़ा जाता है। इसके अलावा, इस अवसर पर 'दुल्ला भट्टी' से जुड़ी लोककथाएं भी गाई जाती हैं।

गुरु मां

DIWALI DHAMAKA Sale

NO COST EMI

ATTRACTIVE EXCHANGE OFFERS

UPTO 55% OFF

UPTO 25% ADD CASHBACK

HOME APPLIANCES पर पाए ऐसे ऑफर्स, खरीदे बिना रूहा ना जाए

Guru Maa Enterprises

RUDRAPUR - 9927882338, Sony Center- 9927396666, KASHIPUR - Ramnagar Road 8791989500, Cheema Chauraha 9927813555, HALDWANI- Tikonia 9997207007, Piliakothi 9690256666, 8126564216, HARIDWAR - 9761699704, MORADABAD - Civil Lines-7500839146, GEE AAR Etc. 9719077772, GADARPUR - Gurunanak Enterprises, 9927850999, KICHHA - Deepak Eletronics 7017575920, ALMORA - Gupta Electronics 7895887544, LALKUAN - New Radhe Radhe 8923493000, PITHORAGHRH - Shiva Enterprises 9760633187, LOHAGHAT - 9568035735, PANIPAT - 8607964000, KARNAL- 8684077000.

अंकिता को न्याय दिलाने के लिए निकाला कैंडल मार्च

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देवभूमि की जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में ट्रांजिट कैंप व्यापार मंडल के आह्वान पर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल और ट्रांजिट कैंप व्यापार मण्डल अध्यक्ष संजीव गुप्ता के संयुक्त नेतृत्व में विशाल कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने ट्रांजिट कैंप कोतवाली के समीप स्थित रक्षा-कृष्ण मंदिर से शिवनगर के चामुंडा मंदिर तक मार्च कर हत्याकांड के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। कैंडल मार्च

के दौरान पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल ने कहा कि अंकिता हत्याकांड के संदर्भ में हाल ही में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के

के घरे से बाहर निकालने के लिए तत्काल भारत सरकार से इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की संस्तुति करनी चाहिए, ताकि वीआईपी के नाम पर बना

है। जब तक इस मामले की तह तक जाकर वीआईपी का चेहरा बेनकाब नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस कैंडल मार्च में विकास बंसल, ललित बिष्ट, रजत गुप्ता, करू मंडल, रामकुमार गुप्ता, सोनू सक्सेना, अनूप, कुलदीप गंगवार, राहुल, जयप्रकाश प्रजापति, गौरव दीक्षित, बाबू राम प्रजापति, हरपाल, राजकुमार, योगेंद्र, राकेश अधिकारी, जितेंद्र राठौर, अरविंद्र गंगवार, कमलदीप सोनकर, सजीव लाला, रविंद्र गुप्ता, मनोज वर्मा, अनिल गुप्ता, यक्ष गुप्ता, राकेश कोली, विजेंद्र पाल, सुरजीत, संजय कुमार, सुरजीत गुप्ता, उमा सरकार, सचिन, सुमित गुप्ता, सुरजीत शर्मा, प्रीति साना, मोनिका ढाली सहित सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी और व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे।



बीच हुई कथित बातचीत में 'वीआईपी' का नाम उजागर होने के बाद से पूरे प्रदेश की जनता स्तब्ध है। टुकराल ने जोर देकर कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार को अपनी छवि स्पष्ट रखने और खुद को संदेह

संशय समाप्त हो सके और मृतका को न्याय मिल सके। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव गुप्ता ने कहा कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी थी और उसकी निर्मम हत्या के बाद से समाज का हर वर्ग दुखी

Alsence®

बवासीर से परेशान?

मल त्यागते समय खून आना, गुदा पर जलन-खुजली, सूजन व मससों की तकलीफ़

अपनाइये 11 साल से भरोसेमंद आयुर्वेदिक समाधान

पाइल्सशोर कैप्सुल

- ✓ केवल 7 दिन में असरदार परिणाम
- ✓ 100% आयुर्वेदिक
- ✓ कोई दुष्प्रभाव नहीं
- ✓ खूनी व बादी बवासीर में लाभकारी

सभी मुख्य मेडिकल स्टोर्स पे उपलब्ध

FOR QUERY CONTACT AT-9997744200, 7536000017